डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.nic.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 60 ● अंक 08 ● भोपाल ● 16-30 सितम्बर, 2016 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/– ● आजीवन शुल्क 1500/–

देश का पहला बिल्डिंग मटेरियल बैंक बनाया जायेगा

राज्य मंत्री श्री सारंग ने आवास संघ के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि राज्य सहकारी आवास संघ को सुदृढ़ बनाने के लिये इसके सिविल विंग को सुदृढ़ बनाया जायेगा। साथ ही देश का पहला बिल्डिंग मटेरियल बैंक स्थापित किया जायेगा। श्री सारंग आवास संघ के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर रहे थे। इस मौके पर श्री अरुण सिंह तोमर, पूर्व अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी संघ उपस्थित थे।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि आवास संघ को घाटे से उबारना और उसे सहकारिता की मुख्य धारा में लाने की एक बड़ी चुनौती है। इसके लिये एक सुनियोजित रणनीति तैयार की गयी है, जिस पर चरणबद्ध अमल किया जायेगा। श्री सारंग ने बताया कि संघ के सिविल विंग को सक्षम और सुदृढ़ बनाया जायेगा ताकि वह डिपाजिट वर्ग के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे सके। इससे संघ आर्थिक रूप से सक्षम होगा। उनका प्रयास होगा कि शासन के अन्य विभाग के निर्माण कार्य के साथ ही सांसद और विधायक–निधि के डिपाजिट वर्ग का काम संघ को

मिले।

देश का पहला बिल्डिंग मटेरियल बैंक बनेगा

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि आवास संघ के अंतर्गत एक बिल्डिंग मटेरियल बैंक बनाया जायेगा, जो देश का पहला ऐसा बैंक होगा। इसके जरिये हम आम लोगों के अलावा शासन के विभिन्न विभाग को निर्माण कार्य के लिये रेत, सीमेंट, गिट्टी और ईंट जैसी निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध करवायेंगे।

सबके लिये मकान

श्री सारंग ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के **सबको मकान** के सपने को पूरा करने में भी आवास संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि नये सहकारिता एक्ट के अनुसार जिन हाउसिंग सोसायटी ने निम्न आय वर्ग के लिये जो भूमि छोड़ी है, उस पर आवास संघ इन वर्गों के लिये मकान बनायेगा।

हाउसिंग सोसायटी के मेंटेनेंस की मॉनीटरिंग होगी

राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में हाउसिंग सोसायटी में मेंटेनेंस को लेकर वहाँ के रहवासियों के बीच काफी समस्या है। इसके निदान के लिये अब विभाग पहल करेगा। मेंटेनेंस की मॉनीटरिंग कर इसमें आने वाली समस्या का समाधान किया जायेगा।

गृह निर्माण समितियों के विवाद का समाधान होगा

श्री सारंग ने बताया कि ऐसी गृह निर्माण समितियाँ, जहाँ पर विवाद की स्थिति है, के सदस्यों को राहत देने के लिये विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। इसमें कोई भी सदस्य अपनी शिकायत दर्ज करवाकर उसका निराकरण कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे अगले माह इसकी समीक्षा करेंगे कि इस नई व्यवस्था से कितने लोगों को लाभ मिला है। अगर कोई कमी होगी, तो उसे दूर किया जायेगा और प्रक्रिया में गति लायी जायेगी।

नवाचार विंग का गठन

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि विभाग में नई ऊर्जा का संचार करने के लिये नवाचार विंग का गठन किया गया है, जिसकी वे हर हफ्ते स्वयं मॉनीटरिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विंग में नवाचार में रुचि और अनुभव रखने वाले लोगों को शामिल किया गया है।

गर्व महसूस हो, ऐसा काम करें

श्री विश्वास सारंग ने आवास संघ के अधिकारी और कर्मचारियों को सकारात्मक भाव से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें नये सिरे से इस संकल्प के साथ काम करना होगा कि हमें संघ की साख को स्थापित करना है। ऐसा काम करना है, जिससे हमें शर्म नहीं गर्व महसूस हो।

प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ हर किसान को मिले

वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग में सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग में सहकारिता के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हरेक किसान को मिले, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस मौके पर आयुक्त सहकारिता श्री मनीष श्रीवास्तव उपस्थित थे।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखकर बनायी गयी है, जो उन्हें संकट के समय मदद प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही न की जाये और किसानों तक इसका लाभ पहुँचाया जाये। श्री सारंग ने विभाग में नवाचार को लेकर किये जा रहे प्रयास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसके जरिये हम एक नई ऊर्जा का संचार कर पायेंगे और सहकारिता से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री ने किसानों को दिये गये ऋण की भी समीक्षा की। उन्होंने खाद–बीज की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित
ई–8/77, शाहपुरा, भोपाल –462039

वार्षिक आमसभा की सूचना

समस्त सदस्य सहकारी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (पंजीयन क्रमांक 4 दिनांक 25–03–1958) की 45वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 26 सितम्बर 2016 को दोपहर 12.00 बजे, संघ कार्यालय ई–8/77, शाहपुरा, भोपाल में आयोजित की गई है। गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक आमसभा आधा घंटे हेतु स्थगित की जाकर उसी दिन, उसी स्थान पर, दोपहर 12.30 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आमसभा में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

टीप: सभी सदस्यों को डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई है। अप्राप्ति की स्थिति में इस विज्ञापन को ही सूचना माना जाये।

प्रबंध संचालक

सहकारिता की मूल भावना सेवा

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना ग्वालियर द्वारा ग्वालियर की सहकारी समिति प्रबंधकों एवं सहायक प्रबंधकों का प्रशिक्षण

ग्वालियर। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना ग्वालियर द्वारा ग्वालियर की सहकारी समिति प्रबंधकों एवं सहायक समिति प्रबंधकों के प्रशिक्षण का अयोजन किया गया। ग्वालियर में पर्यटन भवन सभागर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजकिशोर वाजपेई, संयुक्त आयुक्त न्यायिक सहकारिता थे।

दिनांक 9.8.2016 को घाटीगांव मुरार विकासखण्ड की सहकारी समितियों के समिति प्रबंधकों एवं सहायक समिति प्रबंधकों को सहकारी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्री राजकिशोर वाजपेई, संयुक्त आयुक्त सहकारिता ग्वालियर द्वारा अपने उद्बोधन में प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सहकारिता एक पुनीत कार्य है, क्योंकि इसमें आपके आर्थिक लाभ नहीं सेवा की मूल भावना रहती है, सहकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी प्रबंधकों की नीयत अच्छी है वहां निश्चय ही संस्थाऐं अच्छी है। नीति सरकार बनाती है, नीयत पर आप निर्भर है। प्रशिक्षणार्थियों को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव भोपाल के व्याख्याता श्री अरूण कुमार जोशी तथा नौगांव के श्री गणेश प्रसाद मांझी ने विस्तार से सहकारी सिद्धान्त, समिति की आमसभा, कार्य निर्वाचन, अंकेक्षण सहकारी विधान के प्रमुख संशोधन एवं अधिनियम की जानकारी दी। श्री पी.एन. शर्मा, विकास अधिकारी द्वारा आईसीडीपी की योजनाओं की जानकारी दी।

श्री आर.सी. शर्मा, महाप्रबंधक, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, ग्वालियर ने आई.सी.डी.पी. के सम्बन्ध में समिति प्रबंधकों से विस्तार से चर्चा की तथा आभार व्यक्त किया।

दिनांक 10.8.2016 को डबरा में डबरा, भितरवार विकासखण्ड के समिति प्रबंधकों का प्रशिक्षण आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन डबरा एस.डी.एम. श्री बैश द्वारा किया गया। श्री बैश ने कहा कि आई.सी.डी.पी. द्वारा जो कार्य किये गये है, वो सहकारी संस्थाओं के लिये अत्यन्त आवश्यक थे। प्रशिक्षण का आयोजन एक सार्थक पहल है, डबरा में श्री डी.के. भटनागर विकास अधिकारी द्वारा आई.सी.डी.पी. की योजनाओं की जानकारी दी। आई.सी.डी.पी. के महाप्रबंधक श्री आर.सी. शर्मा द्वारा विस्तार से आई.सी.डी.पी. की योजनाओं पर प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा उमरिया जिले में सहकारी प्रशिक्षण शिविरों का प्रभावी आयोजन

जबलपुर। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा जिला उमरिया शाखा इन्दवार अन्तर्गत सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये। प्रशिक्षण में समिति के सदस्य, पदाधिकारी, समिति प्रबंधक एवं समितियों के लिपिक सहायक, विक्रेताओं ने भाग लिया। शाखा मुख्यालय इन्दवार में बृहद स्तर पर उपस्थित रही, शाखा प्रबंधक श्री सूर्यपाल सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्गम क्षेत्र है, जहां सहकारिता की सेवायें प्रासंगिक है। समस्त कृषक भाई समितियों के सदस्य बनकर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण शून्य प्रतिशत पर प्राप्त करें। साथ ही चालू वर्ष में मुख्यमंत्री जी द्वारा फसल ऋण, खाद बीज वस्तु रूप में लिये गये ऋण पर समय पर वसूली देने पर दस प्रतिशत अनुदान कृषक को दिया जायेगा। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत योजना कृषकों के लिये सरल बनाई गई है। ऋणी कृषकों के लिये बीमा अनिवार्य है। अऋणी कृषक भाई हमारे बैंक के माध्यम से बचत खाता खोलकर फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के व्याख्याता शशिकांत चतुर्वेदी ने सहकारी समिति के संवैधानिक प्रावधानिक प्रावधान, उपनियम तथा संचालक मंण्डल की बैठकें, वार्षिक साधारण सभा के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विपणन संघ के गोदाम प्रभारी श्री मार्को ने विपणन संघ की सेवाओं की जानकारी के साथ भण्डारण का महत्व बताया। वरिष्ठ सहकारी कार्यकर्ता श्री मिश्रा ने समितियों की कार्यप्रणाली में नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा किया।

साधारण सभा सम्पन्न

उज्जैन। सहकारी संस्था नामली के वर्ष 2016–17 की वार्षिक साधारण सभा संस्था अध्यक्ष श्री अशोक राठोड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयीं। वर्ष 2016 में संस्था द्वारा 12.45 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। साथ ही आमसभा की सहमती से लाभ विभाजन अन्तर्गत लाभांश की घोषणा की गयी। गणेशलाल धारवा द्वारा बीमा सम्बन्धी जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा योजना की जानकारी एवं सहमती पत्र के सम्बंध में जानकारी दी गयी। सभा को संचालक श्री पुष्पेन्द्रसिंह पंवार , श्री कीर्तिकुमार जायसवाल, नामली नगर परिषद अध्यक्ष श्री नरेन्द्रकुमार सोनावा, उपाध्यक्ष श्री सुखदेव गेहलोत, संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री बाबुलाल कर्णधार , सदस्य सर्वश्री अम्बाशंकर ठक्कर, श्री भेरूलाल मकवाना, श्री मांगीलाल धारवा द्वारा संबोधित किया गया।

इस अवसर पर संस्था सेवायुक्त श्री मुलचंद्र कुमावत को सेवा निवृत्ति पर साफा, शाल एवं श्रीफल से सम्मानित कर विदाई दी गई। संचालन प्रबन्धक निहार व्यास एवं आभार ईश्वरलाल धारवा द्वारा किया गया।

कीटनाशक लाइसेंस फीस निर्धारित

भोपाल। उप संचालक कृषि विकास विभाग ने बताया है कि कीटनाशक अनुज्ञप्ति फीस 500 रूपये प्रति कीटनाशी एवं अधिकतम साढ़े सात हजार रूपये निर्धारित की गई है । कीटनाशक अनुज्ञप्ति की यह फीस भारत शासन के फरवरी 16 को जारी आदेश से प्रभावशील है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा

नौवे ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड में मध्यप्रदेश सम्मानित

भोपाल। चार बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित मध्यप्रदेश को यहां भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। यह अवार्ड मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने ग्रहण किया। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा आयोजित नौवीं ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अवार्ड दिये गये। कार्यक्रम में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सर्वश्री कप्तान सिंह सोलंकी एवं राम नाईक ने अवार्ड दिये। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति श्री पी.जे. कुरियन एवं भारतीय कृषि और खाद्य परिषद के अध्यक्ष श्री खान और महानिदेशक श्री सिन्हा मौजूद थे।

मध्यप्रदेश ने पिछले 10 वर्ष में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2014-15 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में विकास दर 24.94 प्रतिशत दर्ज की गयी है। यह दर पूरे विश्व में सर्वाधिक आँकी गयी। कुल कृषि उत्पादन 110 प्रतिशत तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में 124 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2004-05 में प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन एक करोड़ 43 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2014-15 से बढ़कर 3 करोड़ 21 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रदेश द्वारा कृषि क्षेत्र में 12 प्रतिशत सालाना दर से एक दशक तक वृद्धि प्राप्त करना देश में अप्रत्याशित घटना है। प्रदेश वर्ष 2004-05 में दलहन फसलों का उत्पादन मात्र 33 लाख 51 हजार मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 47 लाख 63 हजार मीट्रिक टन हो गया। एक दशक में यह वृद्धि 42.14 प्रतिशत आँकी गयी। प्रदेश आज देश में कुल दलहन उत्पादन का 28 प्रतिशत उत्पादित करता है। प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 61 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिवस हो गयी है। यही नहीं कृषि क्षेत्र में भी 34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई। कुल कृषि क्षेत्र बढ़कर 2 करोड़ 23 लाख हेक्टेयर हो गया है।

प्रदेश में फसलों की बोवाई में अभूतपूर्व कीर्तिमान लगातार स्थापित हो रहे हैं। खरीफ-2004 में सोयाबीन का रकबा 45 लाख 94 हजार हेक्टेयर था, जो वर्ष 2013 में बढ़कर 61 लाख 34 हजार हेक्टेयर हो गया। वहीं धान का रकबा वर्ष 2004 में 16लाख 96 हजार हेक्टेयर था, जो वर्ष 2013 में 19 लाख 30 हजार हेक्टेयर हो गया। खरीफ की अन्य प्रमुख फसलें भी वर्ष 2004 की तुलना में लगातार विस्तृत क्षेत्रफल में बोयी जा रही हैं। रबी की बोवाई में भी विगत दस वर्ष में तेजी से प्रगति हुई है। वर्ष 2004 में जहाँ गेहूँ की बोवाई का रकबा 42 लाख हेक्टेयर था, वह 2013-14 में 59 लाख 76हजार हेक्टेयर तक पहुँच गया है। वर्ष 2004 में चना 26लाख 93 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता था, जो वर्ष 2013-14 में 31 लाख 60 हजार हेक्टेयर में बोया गया। रबी 2013-14 के परिणामों के अनुसार गेहूँ का उत्पादन 155 लाख 23 हजार मीट्रिक टन हुआ, जो वर्ष 2004-05 में हुए उत्पादन 73 लाख 27 हजार मीट्रिक टन से लगभग 81 लाख 96हजार मीट्रिक टन अधिक है। अर्थात दो गुना से अधिक उत्पादन वृद्धि हुई। खरीफ-2013 में धान का उत्पादन 53 लाख 61 हजार मीट्रिक टन रहा, जो वर्ष 2004-05 के उत्पादन 13 लाख 09 हजार की तुलना में 40. लाख 52 हजार मीट्रिक टन अधिक है। यह वृद्धि लगभग चार गुना है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के सुचिंतित प्रयासों से आज मध्यप्रदेश देश में कई फसलों के उत्पादन में अव्वल हैं। जैसे कृषि विकास दर, जैविक क्षेत्र, कुल दलहन -तिलहन उत्पादन, प्रमाणित बीज उत्पादन, चना-सोयाबीन उत्पादन, निजी कस्टम हायरिंग-सेंटर की स्थापना, लहसुन-अमरूद और औषधि एवं सुगंधित फसलों, धनिया-मटर और प्याज उत्पादन में देश में प्रथम और कुल खाद्यान्न उत्पादन, गेहूँ उत्पादन, सरसों उत्पादन और मसूर उत्पादन में प्रदेश देश में द्वितीय हैं। गेहूँ उत्पादन में हम चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर, धान में 14वें स्थान से 7वें स्थान पर और मक्का में 6वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए हैं।

अनाज उपार्जन के लिये किसानों के नवीन पंजीयन का कार्य 30 सितंबर तक होगा

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में धान एवं मोटा अनाज उपार्जन के लिये कार्य योजना बनाकर समय सीमा निर्धारित की गई है। इस कार्य योजना और समय सीमा के अनुसार 9 से 30 सितम्बर तक किसानों के नवीन पंजीयन का कार्य किया जायेगा तथा 13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किसानों के पंजीयन के डाटा का सत्यापन संबंधित पटवारी, तहसीलदार, एस.डी.ओ. आदि द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार जिले में 2 नवंबर से 25 जनवरी तक मक्का एवं धान की खरीदी की जायेगी। इस वर्ष पुराने पंजीयनों का नवीनीकरण नही होगा, बल्कि सभी किसानों को नवीन पंजीयन कराना अनिवार्य है।

जिला सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन की आमसभा सम्पन्न

उज्जैन। जिला सहकारी संघ उज्जैन की 55 वीं वार्षिक आमसभा उपायुक्त सहकारिता एवं प्रभारी अधिकारी डा. मनोज जायसवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। आमसभा में संघ का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक पत्रकों एवं वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित कार्यक्रम, वार्षिक बजट, अंकेक्षण आदि की स्वीकृति सभा में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा सर्वानुमति से दी गई। इस अवसर पर डा. जायसवाल ने बताया कि संघ द्वारा वर्ष में जिले में कार्यरत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों जिसमें शहरी साख, गृह निर्माण, बीज, उपभोक्ता भंडारों, नागरिक सहकारी बैंकों, विपणन समितियों के सदस्यों एवं पदाधिकारियों, प्रबंधकों के लिये अलग-अलग शिविरों का आयोजन कर 367 सदस्यों को ई-पोर्टेल, यूजेस नेम वार्षिक आमसभा, कार्यकारिणी के अधिकार/कर्तव्यों के साथ ही कृषि के उन्नत बीज, जैविक खाद, कीटनाशक वाधियों की रोकथाम एवं सहकारी अधिनियम के नवीन प्रावधानों की जानकारी दी गई साथ ही सहकारी सप्ताह का आयोजन जिले की सभी तहसीलों में एवं सहकारी संगोष्टी का आयोजन किया गया एवं जिले की अन्य समितियों की कार्यकारिणी में राज्य संघ के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजित कर 3468 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। सहकारी योजनाओं से संबंधित पेम्पलेट छपवाये जाकर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में वितरित करवाये गये। इस अवसर पर उपस्थित राजपालसिंह सिसौदिया, रामबाबू पाटीदार, भगवानदास गिरी, गजराजसिंह झाला, योगेन्द्र सिंह सिसौदिया, गिरिश शर्मा, राजेन्द्र लाडूना, भालचन्द्र उपाध्याय, कृष्णपाल सिंह, एन.के. राय, मनोहर सिंह झाला, मानसिंह चौहान, दिनेश बैरागी, भूपेन्द्र सिंह, दीनदयाल शर्मा, विनय शाह, नारायण शर्मा, रमेशसिंह रघुवंशी, शांतिलाल चौहान, आर.एल. परमार, संतोष सांकलिया, धर्मराज कोठारी, दिलीप नीमा, सुरेन्द्र मालवीय, दिलीप असरानी, मुकेश जोशी, डा. विजय कुमार जैन, सहायक आयुक्त आर.पी. मिश्रा, कोमल जैन, सुदेश नीमा, शिवपाल सिंह सिसोदिया, जयपाल सिंह, हरिशंकर यादव आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन प्रबंधक जगदीशप्रसाद बैरागी ने किया तथा आभार शिवकुमार गेहलोत ने माना।

'नमामि देवी नर्मदे' अभियान दुनिया में नदी संरक्षण का उदाहरण बनेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अभियान की वेबसाईट लोकार्पित

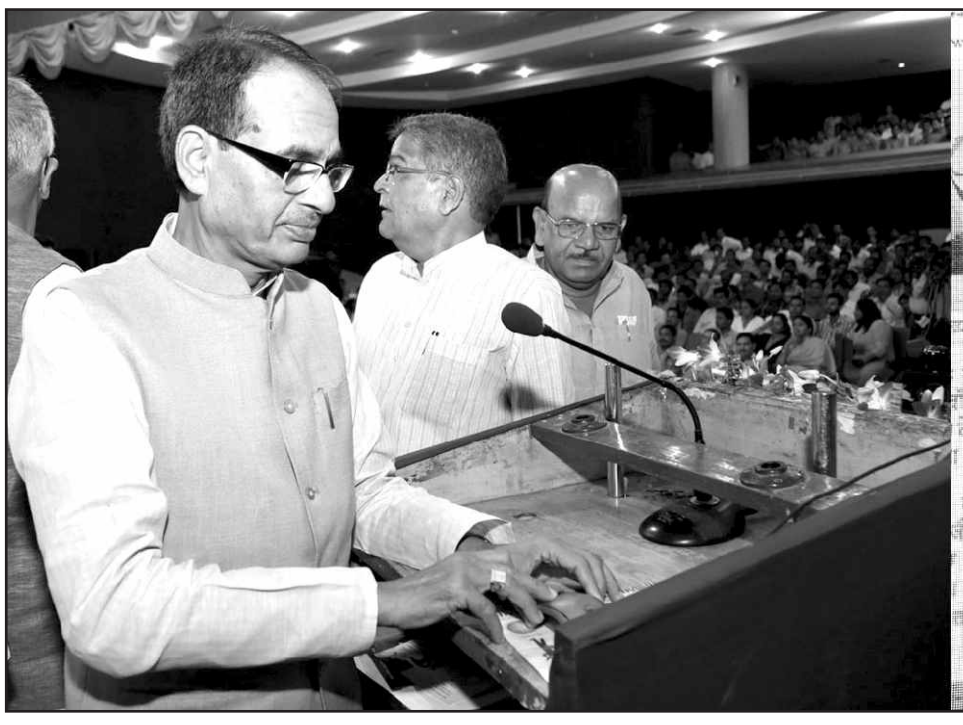

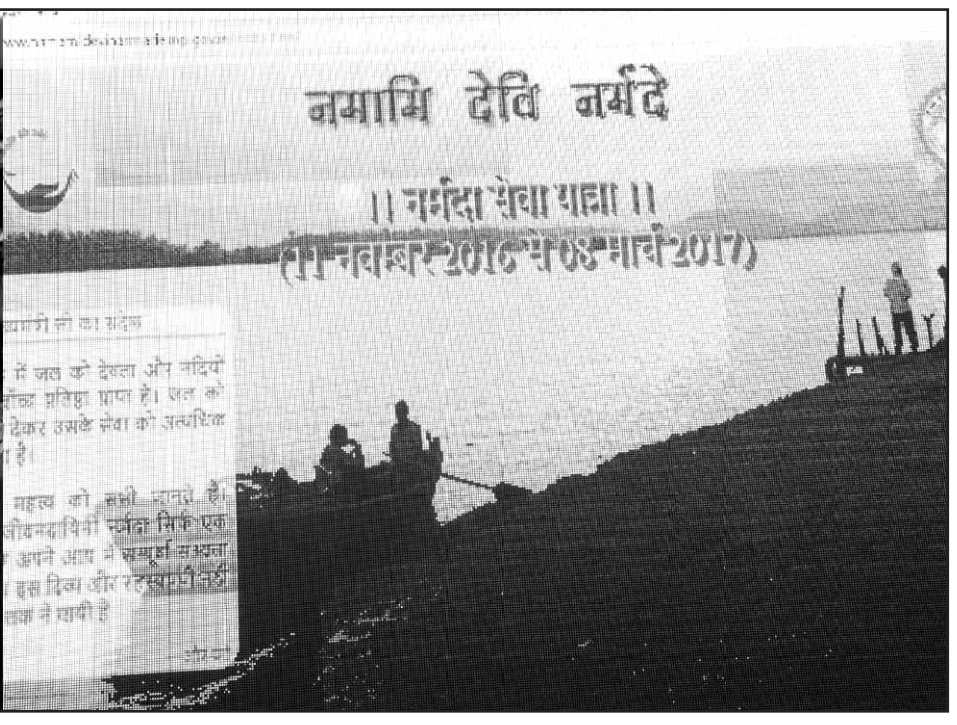

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संपूर्ण समाज की सहभागिता से चलने वाला **नमामि देवी नर्मदे** अभियान पूरी दुनिया में नदी को बचाने का उदाहरण बनेगा। यह अभियान पवित्र जीवनदायिनी नर्मदा नदी के ऋण को उतारने का अभियान है। एक सौ 18दिन चलने वाले इस अभियान में नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर सघन पौधा-रोपण किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान '' नमामि देवी नर्मदे '' नर्मदा सेवा यात्रा की वेबसाईट का लोकार्पण करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नर्मदा गीत, नर्मदा स्लोगन तथा अभियान के प्रतीक चिन्ह के लिये हुई प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है। यह प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बना रही है। यह पेयजल, सिंचाई और बिजली देती है। वृक्षों के कटने से और प्रदूषण से नर्मदा के जलप्रवाह पर प्रभाव हुआ है। इससे नर्मदा को बचाने के लिये व्यापक अभियान चलाया जायेगा। नर्मदा के तट पर ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों मार्गों का संगम होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा के किनारों पर निजी भूमि पर किसानों द्वारा फलदार वृक्ष लगाने पर रा%य सरकार किसानों को इन वृक्षों पर फल आने तक मुआवजा देगी। नर्मदा नदी के संरक्षण और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये जन-जागरण के लिये यात्रा आगामी 11 नवम्बर से निकाली जायेगी। अमरकंटक से लेकर नर्मदा के किनारे आने वाले सभी शहरों-गाँवों से दूषित जल को मिलने से रोकने के लिये ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे। नर्मदा किनारे के सभी ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त किया जायेगा। नर्मदा किनारे के ग्रामों को नशामुक्त बनाया जायेगा।

विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा ने कहा कि **नमामि देवी नर्मदे**, अभियान से नर्मदा नदी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक प्रवाह का माध्यम बनेगी। यह एक जन-जागरण का अभियान है। वन मंत्री डॉ.गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि कृतज्ञता भारतीय संस्कृति का अंग है। नर्मदा नदी जीवनदायिनी है। यह ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का आधार भी है। इस पवित्र नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिये जागरूकता आवश्यक है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित रखने के इस अभियान से समाज का हर वर्ग जुड़े। मध्यप्रदेश ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो कार्यक्रम को सार्थक किया है। कार्यक्रम में पर्यावरण, ग्रामोद्योग और पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग और सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण राज्य मंत्री श्री संजय पाठक विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नर्मदा गीत के लिये प्रथम पुरस्कार श्री महेश श्रीवास्तव, द्वितीय पुरस्कार श्री शक्ति रावत और तृतीय पुरस्कार डॉ. शैलेन्द्र मिश्रा को दिया। इसी तरह स्लोगन के लिये सर्वश्री प्रदीप वर्मा, शिवानी भार्गव, ओमप्रकाश शर्मा, हिमांशु शुक्ला, जितेन्द्र ठाकुर, जयराम खंगार, रमाकांत गुप्ता और सुलभ सिंह को तथा लोगो (प्रतीक चिन्ह) के लिये सुश्री गौरी वंडलकर, श्री भूपेंद्र रोहित और श्री देवाशीष मंडल को पुरस्कृत किया। डॉ. शैलेन्द्र मिश्रा ने पुरस्कार स्वरूप प्राप्त राशि 21 हजार रूपये अभियान में सहयोग के लिये मुख्यमंत्री को सौंपी। जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रदीप पांडेय ने अतिथियों को स्मृति-चिन्ह दिये। आभार प्रदर्शन परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र गौतम ने किया।

कुपोषण से मुक्त होने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा

पोषण आहार सप्ताह में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने की घोषणा

भोपाल। बच्चों के पोषण-स्तर में सुधार लाकर जो भी ग्राम पंचायत कुपोषण से मुक्त होगी, उसे पुरस्कृत किया जायेगा। यह जानकारी महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने पोषण आहार सप्ताह एक से 8 सितम्बर के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अगले एक वर्ष में कुपोषण से मुक्त होने वाली पंचायत को उनकी स्थिति का आकलन कर पुरस्कृत किया जायेगा।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने बताया कि कुपोषण को समाप्त करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें जन-सहभागिता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये विभाग ने पुरस्कार योजना शुरू की है। योजना के अनुसार पुरस्कृत पंचायत के सरपंच को 2100 रुपये, जन-समुदाय अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर 1100 रुपये, आँगनवाड़ी और मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, एएनएम और पंचायत सचिव को 1100-1100 रुपये और ग्राम पंचायत को आदर्श आँगनवाड़ी केन्द्र बनाये जाने पर 5000 की नगद राशि से पुरस्कृत किया जायेगा।

कुपोषण मुक्त पंचायत को घोषित करने के लिये ग्राम पंचायत को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला महिला-बाल विकास अधिकारी को घोषणा-पत्र देना होगा। इसकी पुष्टि थर्ड पार्टी से करवायी जायेगी। आगामी 6 माह से एक वर्ष तक पोषण मुक्त होने की निरंतरता रहने पर ही पुरस्कार दिया जायेगा।

महिला-बाल विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश के पोषण-स्तर में पिछले 10 वर्ष में सकारात्मक सुधार आया है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक वर्ष 2004-05 में 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे, जो घटकर 42.80 प्रतिशत रह गये हैं। देश के अन्य बड़े राज्यों में कुपोषण में आयी कमी से अगर तुलना करें, तो प्रदेश में कुपोषण में भारी कमी आयी है।

बीज का व्यवसाय करने हेतु बीज लायसेंस दिया जायेगा

भोपाल खरीफ एवं रबी सीजन में कृषकों को बोनी हेतु बृहद मात्रा में उन्नत बीजों की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति बीज का व्यवसाय करना चाहते हैं वे बीज लायसेंस से संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा कर लायसेंस प्राप्त कर सकते हैं । अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुकम्पा नियुक्ति के एवज में अनुग्रह राशि बढ़कर दोगुना हुई

समाधान ऑनलाईन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण को किया निलंबित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को आगाह किया है कि जन-समस्याओं के निराकरण के मामलों में लापरवाही के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी। श्री चौहान समाधान ऑनलाईन में प्राप्त जनशिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति नहीं लेने वाले परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रूपए करने और पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति की राशि भी सीधे छात्रों के खाते में जमा होने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर 13 आवेदकों की समस्याओं का समाधान हुआ। योजनाओं के लाभ में विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। ग्वालियर जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण को निलंबित कर, शाजापुर के सेवानिवृत्त तत्कालीन पटवारी और नायब तहसीलदार को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं का लाभ हितग्राही को बिना भटके मिले। इसमें किसी तरह की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। जिला स्तर पर ही आमजन की समस्याओं का प्रभावी निराकरण हो जाये। ऐसा नहीं होने पर संबंधित जिला कलेक्टरों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाईन और लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त समस्याओं को चिन्हित कर उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में पुनः ऐसी शिकायतें मिलेगी तो संबंधित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात को पुनः दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार जड़-मूल से समाप्त किया जाये। इस संबंध में जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी हो, की जाये। भ्रष्टाचार के प्रकरण मिले तो यह माना जायेगा कि वरिष्ठ अधिकारियों की भी सहमति है। उन्होंने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर अविलंब लाभ मिलने की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल बीमा की राशि का वितरण किसान सम्मेलन आयोजित कर और बैंक खातों में सीधे राशि जमा होने वाली योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मेलन कर, स्वीकृति पत्र दिये जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक, मंत्री को भी सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाए जिससे योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो और भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं रहे।

श्री चौहान ने मौसमी बीमारियों के बचाव एवं उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। अधिकारियों को दवाओं का समुचित भंडारण करने और उपचार की समुचित व्यवस्था के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रशासनिक अधिकारी समाज के साथ सतत सीधा संवाद बनाए रहे। सज्जनों के साथ मधुर और दुष्टों के साथ कठोर व्यवहार किया जाए। नागरिक सुरक्षा सर्वोच्च है।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला सहित अपर मुख्य सचिव एवं विभिन्न विभाग के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से एल.ई.डी. बल्ब का वितरण

भोपाल। उजाला योजना को गांव-गांव तक पहुंच को दृष्टिगत वर्तमान में जिला सहकारी बैंक विदिशा, रायसेन, दमोह, देवास तथा उज्जैन के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा एल.ई.डी. बल्ब का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में 9 वॉट एल.ई.डी. बल्ब का वितरण किया जा रहा है। उक्त योजना का प्रदेश में शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को किया गया था।

उजाला योजना के अंतर्गत राज्य में 9 वॉट क्षमता के उच्च गुणवत्ता एवं ऊर्जा दक्ष एल.ई.डी. बल्बों का वितरण मात्र 85 रुपये प्रति बल्ब की दर पर किया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत रु. 250/- से 300/- रुपये है। 9 वॉट का यह बल्ब 100 वॉट के साधारण बल्ब के समान प्रकाश देता है, अर्थात् इसके प्रयोग से बिजली की 91 प्रतिशत बचत है।

किसी भी पहचान पत्र के आधार पर कोई भी, यथा, घरेलू/वाणिज्यिक/औद्योगिक/शासकीय/अर्द्ध शासकीय उपभोक्ता असीमित संख्या में बल्ब क्रय कर सकेगा।

आयुक्त सहकारिता ने उक्त ईल.ई.डी. बल्ब प्रदेश की सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरण किये जा सकने हेतु निर्देशित किया है तथा अपेक्षा की है कि कोई सहकारी संस्था इच्छुक हो तो वह व्यवसाय कर लाभ अर्जित कर सकती है।

सहकारिता नवाचार में गठित संस्थाओं का प्रशिक्षण सम्पन्न

उज्जैन। जिला सहकारी संघ उज्जैन के प्रबंधक श्री जगदीश प्रसाद बैरागी ने बताया कि जिले में सहकारिता में हुए नवाचार अंतर्गत गठित परिवहन, पर्यटक, सेवा प्रदाता, रहवासी एवं जैविक, उघानिकी के अध्यक्ष/ संचालक/ संगठकों/प्रबंधकों का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण डा. मनोज जायसवाल, उपायुक्त्त, सहकारिता के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डा. जायसवाल द्वारा सहकारी संस्थाओं के संचालन, निर्वाचन के साथ ही नवाचार में गठित संस्थाओं के लाभ की जानकारी दी।

नव नियुक्त राज्यपाल श्री कोहली का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश के नव नियुक्त राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली को मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन ने आज पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन परिसर में 12:30 बजे आयोजित किया गया। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। राज्यपाल श्री कोहली को शपथ ग्रहण के पश्चात गार्ड ऑफ आनर दिया गया। श्री कोहली ने सलामी गारद का निरीक्षण भी किया।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक शामिल हुए। इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरन शर्मा, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष श्री बाला बच्चन, पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, प्रदेश मंत्रीमंडल के सदस्य, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा,सांसद,विधायक, उप लोकायुक्त श्री ए.के. महेश्वरी, मुख्य सूचना आयुक्त श्री के.डी.खान, वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमेन शौकत मोहम्मद खान, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अरूण यादव, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विश्वविद्यालयों के कुलपति, सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पत्रकार उपस्थित रहे।

आजीविका मिशन के नवाचार अन्य प्रदेशों में भी अपनाये जा रहे हैं

बैंक सखी योजना को मिली राष्ट्रीय-स्तर पर सराहना

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सफल क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों के फलस्वरूप उसके नवाचारों को राष्ट्रीय-स्तर पर अन्य प्रदेशों द्वारा अपनाया जा रहा है। बैंक सखी योजना को नई दिल्ली में कार्यशाला में प्रेजेन्टेशन के दौरान सराहना मिली और अन्य प्रदेशों में भी अपनाये जाने की सिफारिश की गयी। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद में राज्य-स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर में भी इस योजना की सराहना की गयी।

मिशन द्वारा प्रदेश में महिलाओं को संगठित कर प्रशिक्षण एवं समूह सदस्यों के परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये हैं। इसकी प्रशंसा शहडोल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी की गयी।

बैंक सखी योजना में गाँव की शिक्षित महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया के लिये अधिकृत किया गया है। गाँव-गाँव जाकर बैंक में खाते खुलवाने का काम किया गया। इसके लिये उन्हें बैंक से कमीशन भी दिया गया। जब बैंक सखी का काम ठीक लगा तो बैंकों ने उन्हें प्रोत्साहन राशि देना भी शुरू कर दिया। अब प्रदेश में लगभग 500 बैंकिंग कॉरेस्पान्डेन्ट्स ग्रामीण महिलाओं के रूप में तैनात करने की तैयारी आजीविका मिशन द्वारा की जा रही है। बड़वानी, राजगढ़ और अलीराजपुर में 158 गाँव के समूह-सदस्यों को बैंकों की भाग-दौड़ से मुक्ति दिलवाने के उद्देश्य से बैंकिंग कॉरेस्पान्डेन्ट्स की तैनाती की गयी है। इससे वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी तथा महिलाओं की आजीविका में प्रगति होगी।

प्रदेश में आजीविका मिशन की शुरूआत अप्रैल, 2012 में की गयी थी। मिशन द्वारा ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाओं के सशक्त स्व-सहायता समूह बनाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के अवसर मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है।

बैंक एवं पोस्ट ऑफिस जॉब कार्डधारियों को कैम्प लगाकर मजदूरी का भुगतान किया जाए

भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत 2017-18 का लेबर बजट निर्माण एवं कार्यो के चिन्हांकन के लिए आयुक्त मनरेगा श्री रघुराज राजेन्द्रन ने निर्देशित करते हुये कहा है कि प्रत्येक ग्राम में जल संग्रहण के 2 कार्यों का चिन्हांकन हो, प्रत्येक ग्राम पंचायत मे मुक्तिधाम, खैल मैदान, पंचायत भवन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति मोहल्ले में सीसी रोड एवं खुले से शौच मुक्त ग्राम पंचायतों में नाडेप तथा बर्मी कम्पोस्ट के कार्यों को प्राथमिकता से शामिल किया जाये ।

राजेन्द्रन ने जॉब कार्डधारियों को समय से बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के द्वारा मजदूरी भुगतान न किये जाने पर निर्देश जारी करते हुये कहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कलस्टरवार महिने में एक दिन निर्धारित करते हुये बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधी राशि वितरण के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर व्यवस्था सुनिश्चित करें। मजदूरी भुगतान के लिए रोजगार संवाद दिवस का चयन किया जाये । साथ ही कैम्प लगाकर जिला एवं जनपद पंचायत स्तरीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति मे जॉब कार्डधारियों को सूचित करते हुये कार्यवाही की जाये जिससे बैक एवं पोस्ट ऑफिसो में जारी राशि समय से श्रमिको को मिल सके।

एक तालाब में झींगा मछली का विशेष प्रयोग करें

मछली-पालन मंत्री श्री आर्य के मत्स्य महासंघ को निर्देश

भोपाल। पशुपालन एवं मछली-पालन मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य ने मत्स्य महासंघ को एक तालाब में केवल झींगा उत्पादन का विशेष प्रयोग करने को कहा है। श्री आर्य ने कहा कि झींगा बाजार में 800 से 1000 रुपये किलो तक बिकता है। यदि प्रयोग सफल रहा तो मत्स्य-पालकों की आमदनी में अच्छी बढ़ोत्तरी हो सकेगी। श्री आर्य ने यह निर्देश मत्स्य महासंघ की काम-काज समिति की बैठक में दिया। संचालक मत्स्योद्योग श्री ओ.पी. सक्सेना और प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ श्री सतीश सिलावट भी बैठक में मौजूद थे।

श्री आर्य ने मत्स्य विक्रय अनुबंधों के प्रावधानों, संघ की जुलाई, 2016 तक की मत्स्य-पालन गतिविधियों, अगले वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित कार्यक्रम एवं लक्ष्य, पिछले वित्त वर्ष के प्रस्तावित लाभ के विभाजन एवं लाभांश वितरण आदि के संबंध में चर्चा कर निर्देश दिये। बैठक में राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ की वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की वार्षिक आमसभा की बैठक में भाग लेने के लिये प्रबंध संचालक या सचिव को नामांकित किया गया। राष्ट्रीय संघ टेरिटरी में मध्यप्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।

बैठक में महासंघ के भोपाल स्थित मुख्यालय भवन के नवीनीकरण पर भी चर्चा की गयी। नवीनीकरण के लिये 36 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है। नवीनीकरण कार्य वर्षा ऋतु समाप्त होते ही आरंभ होगा। श्री आर्य ने कहा कि कार्य पारदर्शी तरीके से हो और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाये।

कृषक कीट प्रकोप पर नजर रखें

भोपाल। कृषक अपने खेतों का नियमित भ्रमण करें तथा रोग अथवा कीट का प्रकोप दिखाई दे तो तत्काल संज्ञान में लेकर उसका उपचार करें। यदि इल्ली का प्रकोप दिखाई दे तो कीटनाशक दवा क्विनालफॉस, 1.5 लीटर प्रतिहेक्टेयर या इण्डोक्साकार्ब 500 मिलि लीटर प्रतिहेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। भृंग,गर्डल.बीटल, दिखाई दें, तो इसके नियंत्रण हेतु ट्रायजोफॉस 800 मिलि लीटर का छिड़काव करें।

प्रदेश में पूंजी निवेश के लिये बेहतर वातावरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान की ब्रिटिश हाई कमिश्नर श्री अय्यर से मुलाकात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पूँजी निवेश के लिये बेहतर वातावरण, उद्योग मित्र नीति और अधोसंरचना उपलब्ध है। मध्यप्रदेश निवेश के लिये आदर्श प्रदेश है। मुख्यमंत्री श्री चौहान से यहाँ मंत्रालय में ब्रिटिश हाई कमिश्नर श्री कुमार अय्यर ने मुलाकात की। इस दौरान डी.एफ.आई.डी के कन्ट्री हेड श्री मार्शल इलियट भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज मध्यप्रदेश देश का सबसे तेजी से विकसित प्रदेश है। मेक इन एम.पी. कार्यक्रम के लिये आगामी अक्टूबर माह में ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट आयोजित की जा रही है। डी.एफ.आई.डी के माध्यम से इंग्लेंड प्रदेश में बहुत पहले से कार्य कर रहा है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिये होने वाली उनकी इंग्लेंड यात्रा का फोकस स्मार्ट सिटी और स्किल डेव्हलपमेंट रहेगा। प्रदेश के सात शहर का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्मार्ट बनाया जायेगा। प्रदेश में अगले तीन वर्ष में नगरीय विकास के क्षेत्र में 75 हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में समूह पेयजल योजनाओं पर 18 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। प्रदेश में ई-टेंडरिंग की पारदर्शी प्रणाली लागू है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इंग्लेंड से अधिक से अधिक निवेशक शामिल हो। लन्दन में यू.के. इन्वेस्टर्स बिजनेस काउंसिल के सहयोग से इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जायेगी। निवेश के साथ रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने पर जोर है।

चर्चा के दौरान ब्रिटिश हाई कमिश्नर श्री अय्यर ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इंग्लेंड पार्टनर कंट्री रहेगा। इंग्लेंड द्वारा देश में तीन स्मार्ट सिटी के लिये सहयोग किया जा रहा है, उसमें इंदौर शामिल है। स्मार्ट सिटी के अलावा वाटर ट्रीटमेंट और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग किया जा सकता है। इंग्लेंड के विदेशी पूँजी निवेश का दस प्रतिशत भारत में निवेशित है। उनके देश की औद्योगिक कम्पनियाँ गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। ये कंपनियाँ मध्यप्रदेश में आ सकती हैं। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा और सचिव श्री विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे।

रोजगार केबिनेट का गठन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रोजगार मामलों की मंत्रि-परिषद समिति (रोजगार केबिनेट) का गठन किया गया है। समिति में वित्त मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, वन मंत्री, महिला-बाल विकास मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, राज्य मंत्री पर्यटन और राज्य मंत्री सूक्ष्म एवं लघु एवं उद्योग सदस्य होंगे। वाणिज्य-उद्योग एवं रोजगार विभाग समिति का नोडल विभाग रहेगा। मुख्य सचिव समिति के सदस्य सचिव होगें। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग इस समिति में सह-सचिव होंगे।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सिंचाई के जल का हो पूरा उपयोग

जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश

भोपाल। जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सिंचाई योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। मंत्री डॉ. मिश्रा ने निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के काम जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव जल संसाधन श्री पंकज अग्रवाल और प्रमुख अभियंता श्री एम.जी.चौबे उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सिंचाई के जल का किसानों के हित में पूरा उपयोग हो। वर्षा जल और अन्य जल स्त्रोतों से व्यर्थ बहने वाले पानी के अधिकतम उपयोग की दिशा में प्रयास निरंतर किए जाएं। उन्होंने प्रदेश की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को दी जा रही सिंचाई सुविधा की जानकारी प्राप्त की। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि जिन परियोजनाओं में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है, उनकी स्वीकृति के लिए तीव्र गति से प्रयास किए जाए। हरसी उच्च-स्तरीय नहर को दोआब नहर से सीधे जल प्रदाय करने की योजना बनायें। डॉ. मिश्रा ने कहा कि लोअरगोई परियोजना की वन, पर्यावरण एवं प्रशासकीय स्वीकृति वरीयता से प्राप्त की जाए।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने ग्वालियर और दतिया क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं की भी जानकारी ली। ग्वालियर नगर में जल प्रदाय के लिए उपयोग में लाए जा रहे तिघरा जलाशय पर दबाव कम करने के लिए मणिखेड़ा जलाशय के उपयोग के लिए भी योजना तैयार करने को कहा। इसी तरह दतिया शहर में जल प्रदाय और सुधार के लिए नगरीय प्रशासन विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजल आपूर्ति में जल संसाधन विभाग की भूमिका सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश

मेक इन इंडिया का प्रवेश द्वार

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

वैश्विक निवेशक सम्मेलन

22-23 अक्टूबर, 2016

ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर

अधिक जानकारी वेबसाइट
www.investmp.com
पर उपलब्ध

Organised By TRIFAC | National Partner CII Confederation of Indian Industry | Knowledge Partner EY Building a better working world

सरल प्रक्रिया... असीमित अवसर...

D-79660/2016

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2016

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।